के अनुसूचित उद्योगवार ब्यौरे को दर्शानेवाला एक विवरण अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट सं० CLXVIII अनुपत्र सं० 35]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जन-शक्ति का युक्तिसंगतीकरण किया जाना

2185. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जनशक्ति के युक्तिसंगतीकरण करने हेतु क्या प्रयास किये हैं; और

(ख) इस दिशा में सरकार को कितनी सफलता मिली है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को संघ के अन्तर्नियमों के तहत अपनी आवश्यक तदनुसार अधिकारियों व कर्मचारियों को नियुक्त करने और उन्हें हटाने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए मानवशक्ति के यौक्तिकीकरण का उत्तरदायित्व सरकारी क्षेत्र के संबद्ध उपक्रमों के निदेशक मण्डलों पर है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयासों का विवरण नीचे दिया गया है :—

(i) नवीकरण/पुनर्स्थापन संबंधी योजना तैयार करने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल में सरकारी क्षेत्र के 44 रुग्ण उपक्रमों का पंजीकरण करना।

(ii) मानव शक्ति के यौक्तिकीकरण के उद्देश्य से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-योजना आरम्भ करना।

यौक्तिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और इसकी सफलता का इतनी जल्दी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। बहरहाल पिछले तीन वर्षों के दौरान जब तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान सरकारी उद्यमों में कर्मचारियों की कुल संख्या नीचे दी गई है :—

समाप्त वर्ष	कर्मचारियों की संख्या (लाखों में)
31-3-1991	22.36
31-3-1991	22.19
31-3-1992	21.84

लघु उद्योगों का विस्तार

2186. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों को स्थापित करने तथा उनके विस्तार के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किराया-खरीद आधार पर मशीनरी की आपूर्ति करने हेतु कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा गुजरात में क्या-क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इन राज्यों में इन सुविधाओं से गत वर्ष में लघु उद्योगों तथा उनमें नियोजित कर्मकारों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

Assistance ID Stales for revival of sick industries

2187. SHRI S. AUSTIN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the total assistance provided by the Union Government to each State during each of the last three years for the revival of sick small scale industries; and

(b) the assistance proposed to be given for 1992-93, State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY DEPTT. OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) The amount sanctioned by the Union Government under the margin money scheme for the revival of sick small scale industries was Rs. 10 lakhs during 1989-90 to the State of Uttar Pradesh, Rs. 28 lakhs to the State of Kamataka during 1990-91, Rs. 3.37 lakhs and Rs. 24.62 lakhs to the States of Rajasthan and Tamil Nadu respectively during 1991-92. During 1992-93, the amount of Rs. 15.67 lakhs was sanctioned to the State of Kamataka. Other States except those mentioned above have not claimed any such assistance during the last 4 years under the scheme. Besides the banks are also helping in revival of sick units as per RBI guidelines.

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड में कर्मकारों की बकाया राशियां

2188. **श्री राम नरेश यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड में चेयरमैन, सहायक प्रबन्ध निदेशक सहित अन्य पदों के लिये चयन कर लिया है; और भविष्य में इन पदों को कब तक भरे जाने की सम्भावना है;